जलागम दर्पण

हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना

।। वनं रक्ष, जलं रक्ष, रक्ष धरां च ।।

त्रिमासिक पत्रिका

अंक - 03, जुलाई-सितम्बर, 2009 निः शुल्क केवल सीमित वितरण हेतु

जन सहभागिता

सतत् विकास, संकल्प, सहभागीता एवं पारदर्शिता...

मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना की उच्च स्तरीय बैठक शिमला में दिनांक 21 अगस्त, 2009 को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री जगत प्रकाश नडड़ा, माननीय वन मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा की गयी। इस बैठक में श्री अभय शुक्ला, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), प्रधान मुख्य अरण्यपाल श्री विनय टण्डन, श्री आर0के0कपूर, मुख्य परियोजना निदेशक तथा अन्य विभागीय व परियोजना के अधिकारी द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक में परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई।

परियोजना की अभी तक की प्रगति रिपोर्ट को पेश करते हुए अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक श्री आर0के0कपूर, ने जानकारी दी कि यद्यपि परियोजना के तहत 602 पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से सम्मिलित किया जा रहा है। अब तक 550 ग्राम पंचायतों में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2008-2009 तक कुल 140.30 करोड़ रूपये व्यय किए गए हैं, जिसमें संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर 17.53 करोड़, जलागम विकास एवं प्रबन्धन के अर्न्तगत 90.94 करोड़ इसी प्रकार आजीविका वर्धन कार्यक्रम के अर्न्तगत 3.83 करोड रूपये तथा परियोजना समन्वय पर 27.94 करोड़ रूपये की धन राशि व्यय की गई है। आधुनिक परिवेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की महत्वता को देखते हुये हाल ही में विकसित एवं स्थापित किये गये प्रबन्धन एवं सूचना पद्धति (एम.आई.एस.) व वित्तीय प्रबन्धन पद्धति (एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर परियोजना को और गतिशीलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। इसी प्रकार गाद व वर्षा मापक स्वचालित यंत्रों की स्थापना से परियोजना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन सिल्ट ऑबजरवेशन पोस्ट स्टेशनों की मदद से परियोजना द्वारा विभिन्न जलागम विकास एवम् उपचार गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया जा सकेगा।

पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ करने तथा वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायतों को उपदान (GIA) के रूप में 33.52 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी प्रकार सहभागिता के आधार पर लाभार्थी अंश के रूप में 6.59 करोड रूपये प्राप्त हुए हैं, जिसे ग्राम पंचायतों के रख रखाव कोष में जमा किया गया है। परियोजना को जलागम पद्धति के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।

परियोजना की अभी तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए माननीय वन मन्त्री हिमाचल प्रदेश ने परियोजना की प्रगति पर सन्तोष व्यक्त किया तथा जनसहभागिता एवं पारदर्शिता को मुख्य रूप से परियोजना में अपनाने पर परियोजना की सराहना की । उन्होंने नई पंचायतों को परियोजना में चरणबद्धतरीके से सम्मिलित करने की प्रक्रिया को तुरंत आरम्भ करने के आदेश दिये। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना के मध्यवर्ती समीक्षा हेतु आधिकारियों को तैयार रहने का आह्वान किया और उन्होंने सुझाया कि परियोजना की सफलता का सही मूल्यांकन लाभान्वित परिवारों की अभिव्यक्ति से ही किया जा सकता है।

" परियोजना की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन लाभान्वित परिवारों की स्वेच्छा से की गई अभिव्यक्ति से ही किया जा सकता है "

श्री जगत प्रकाश नडड़ा
माननीय वन मन्त्री हिमाचल प्रदेश

शिमलाः परियोजना की उच्चस्तरीय प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते माननीय वन मन्त्री, हिमाचल प्रदेश श्री जगत प्रकाश नडड़ा जी

मुख्य परियोजना निदेशक की ओर से ....

सम्पादकीय

मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना में मुख्यतः जल प्रबन्धन को केन्द्र बिन्दु मानकर किसान भाईयों को उच्च मूल्य की फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। परियोजना को ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें परियोजना एक सुगम कर्ता की भूमिका निभा रही है। विशेषकर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे कि महिलाएं, भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति समुदाय आदि के लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाकर प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता द्वारा आत्म निर्भर बनाया जा रहा है । ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र की ग्रामीण जलागम विकास योजना को बनाने, लागू करने एवं विकास कार्यों के रख रखाव में हर स्तर पर पारदर्शिता तथा जन सहभागिता को अपनाया जा रहा है ।

पुराने गावों की परम्पराओं के अध्यन्न करने से ज्ञात होता है कि हमारे गांवों के नियोजन एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के लिये पारम्परिक सामाजिक व्यवस्थाएं थी जिस से किसी भी विशेषज्ञ के बिना भी गांव मे समग्र विकास होता था। सामूहिक कार्यों को मिलजुल कर पूरा किया जाता था जिसे हम अब सहभागिता के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम देखतें हैं कि ग्राम स्तरीय नियोजन की पद्धति पहले बहुत मजबूत थी। जहां एक ओर विकास कार्यों को मूर्तरूप देना आवश्यक है, वहीं सभी प्रतिभागीयों को हर स्तर पर सोचने ,विश्लेषण करने तथा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा हर प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान अति आवश्यक है, जिससे सभी सम्बन्धित प्रतिभागियों (Stakeholders) को परियोजना को समझने व इस की कार्य प्रणाली के बारे आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके ।

वर्तमान आधुनिक परिवेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की महत्वता को देखते हुये प्रबन्धन एवं सूचना पद्धति (MIS) व वित्तीय प्रबन्धन पद्धति(FMS) का अपना अलग ही महत्व है। इन दोनों सॉफ्टवेयरों को विकसित कर स्थापित किया गया है । यह सॉफ्टवेयर परियोजना को गतिशीलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जहां एक ओर इन से विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करने, सहजने व विश्लेषण करने में होने वाली समय की व्यर्थता कम होगी वहीं दूसरी ओर सूचनाओं में सटीकता आयेगी एवं सम्बन्धित सभी पक्षों में पारदर्शिता एवं जबाबदेही भी बढेगी। इसी प्रकार परियोजना में परस्पर सम्पर्क के लिये अधिक से अधिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों व विधियों का प्रयोग किया जा रहा है जिस से कार्य निष्पादन में आसानी व सहजता बढी है। विभिन्न सूचनाओं से सुसज्जित परियोजना की बैव साईट का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी छोर से परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी वाछित जानकारी अपने कम्प्यूटर के माऊस की एक हल्की सी क्लिक की आवाज पर प्राप्त कर सकता है ।

मेरा विश्वास है कि यह सभी छोटे. छोटे कदम मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगे ।

आपका स्नेहील - आर.के. कपूर, भा.व.से.,
मुख्य परियोजना निदेशक

नयी दिशाऐं

श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार

मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना प्रदेश के 10 जिलों के 42 विकास खण्ड़ों की 602 पंचायतों में विश्व बैंक की सहायता से संचालित की जा रही है। जिस के तहत 5.20 लाख हैक्टेएर भूमि उपचारित की जायेगी । इस परियोजना का मुख्य उददेश्य प्राकृतिक संसाधनों में निरन्तर हो रहे क्षरण की प्रकिया में कमी लाना, प्राकृतिक संसाधनों की उत्पादक क्षमता में बढ़ौतरी करना व साधन विहीन निर्धन ग्रामीण परिवारों विशेषकर आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे कि महिलाएं, भूमिहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति समुदाय आदि के लोगों को स्वयं सहायता समूह बनाकर प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है। यह एक एकीकृत जलागम विकास परियोजना है, जिसमें जलागम को कृषि, पशुपालन, बागवानी, वन, भू-सरंक्षण एवम् ग्रामीण विकास कार्यों में जनसहभागिता के आधार पर विकसित किया जा रहा है । पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ करने के लिये मुख्यतः परियोजना को ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और परियोजना एक सुगम कर्ता की भूमिका निभा रही है । ग्राम पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र की ग्रामीण जलागम विकास योजना को बनाने, लागू करने एवं विकास कार्यों के रख-रखाव में हर स्तर पर पारदर्शिता तथा जन सहभागिता को अपनाया जा रहा है । इस उददेश्य की पूर्ति के लिए अभी तक 1784 स्वंय सहायता समूह एवं 2134 उपभोगता समूहों द्वारा परियोजना की जलागम पद्धति के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के सतत् विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं सुदृढ़ करने तथा वास्तव में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायतों को परियोजना संचालन के लिये उपदान (GIA) के रूप में धन उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार

जलागम परियोजना द्वारा प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता द्वारा विकास कार्यो में जन सहभागिता।

सहभागिता के आधार पर हर कार्य के लिये लाभान्वित परिवारों से लाभार्थी अंश के प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसे ग्राम पंचायतों के रख रखाव कोष में जमा किया जाता है ।

इन पुरस्कारों के लिये सभी ग्राम पंचायतों को परियोजना के मुख्या घटकों जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रबन्धन तथा संरक्षण, वनों का उचित प्रबन्धन, आजीविका उपार्जन के साधनों का विस्तार, संस्थागत विकास में सहयोग तथा कार्य में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली श्रेष्ठ पंचायतों को प्रति वर्ष दिया जाएगा। इस प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल 14 पुरस्कारों को प्रतिवर्ष 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेष्ठ जलागम पंचायतों को क्रमशः 4.00 लाख, 2.50 लाख तथा 1.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा मण्डल स्तर पर प्रत्येक मण्डल की सर्वश्रेष्ठ प्रथम पंचायत को एक-एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जायेंगे। इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग इन पंचायतों द्वारा अपनी ग्राम पंचायत में संरचनात्मक विकास कार्यों में व्यय किया जाएगा।

ग्राम पंचायतों को परियोजना कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रोत्साहन के रूप में राज्य एवं मण्डल स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कारों से अलंकृत करने का प्रावधान विश्व बैंक के सहयोग से किया गया है। जहां एक ओर इन पुरस्कारों से आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढती है, वहीं दूसरी ओर परियोजना के सर्वोतम कार्यान्वयन के लिये जवाबदेही एवं पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेता है। इसी कड़ी में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना के लिये प्रदेश में 8 अगस्त 2009 को पहली बार इन पुरस्कारों का वितरण राज्य स्तरीय 60वां भव्य वन महोत्सव समारोह शिमला के ऐतिहासिक गेयटी सभागार में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया गया। दृढ संकल्पित पर्यावरण समर्पित माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इन पुरस्कारों को वितरित करने में जहां एक ओर प्रसन्नता जाहिर की वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रोत्साहनों को अधिकाधिक प्रचारित करने का आवहान किया। इस वर्ष ग्राम पंचायत शेरपुर विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा की प्रधान श्रीमति नीलम देवी जी को प्रथम राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार से अलंकृत किया गया। द्वितीय राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार से ग्राम पंचायत जरी विकास खण्ड एवं जिला कुल्लू की प्रधान श्रीमति प्रेम कुमारी जी को सम्मानित किया गया तथा ग्राम पंचायत कुन्नू विकास खण्ड दरंग, जिला मण्डी के प्रधान श्री कर्म चन्द जी को तृतीय राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार से सुशोभित किया गया।

टी.सी.कौण्ड़ल,
मण्डलीय जलागम विकास अधिकारी,सोलन एवं
परियोजना जन सम्पर्क अधिकारी

बढ़ते कदम ....

रामपुर भलोरी किसान समूह की कहानी
ग्रम पंचायत कृष्णगढ़, जिला सोलन

बिन पानी सब सून.....

देव भूमि हिमाचल प्रदेश के आंचल में बसा जिला सोलन अपनी पर्वतीय छटा के लिए प्रसिद्ध है। इसी जिला के अर्न्तगत रमणीय, शांत एवं शौम्य स्थल कसौली के समीप स्थित है, एक प्यारा सा नन्हा गांव कृष्णगढ़ जिसे पहले कुठाड के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णगढ़ एक रियासत थी जिसका नाम राजा किशन चन्द के नाम पर रखा गया था । ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ के अर्न्तगत दो गांव में लगभग 104 बीघा कृषि भूमि है, जिस में से केवल 24 बीघा सिचिंत भूमि थी एवं शेष 80 बीघा भूमि असिंचित थी। यह भूमि केवल वर्षा पर निर्भर थी । क्षेत्र के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर थे । सिंचाई का उचित प्रबन्ध या साधन न होने के कारण कृषि के साथ-साथ मजदूरी करने के लिए बाहर जाने के लिये विवश होना पडता था। लगभग 60 वर्ष पूर्व इस गांव में मात्र कच्ची कूहल द्वारा पानी आता था। अधिकतर लोग परांपरिक फसलों गेहूं, मक्की तथा धान की खेती किया करते थे । नकदी फसलों की ओर ग्रामंवासियों का रुझान बहुत कम था। वर्ष 1990 में भू -संरक्षण विभाग इकाई द्वारा भलोरी, जारु जल स्त्रोत से इन दोनो गांवों को कच्ची कूहल के स्थान पर सीमेंट के पाईप से सिंचाई की योजना स्थापित की गई इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्रामवासियो की एक कमेटी भी बनाई गई । इन पाईपों द्वारा 3 वर्ष तक ही ग्रामवासियों को पानी सफलता पूर्वक उपलब्ध हो सका। इसके पश्चात अधिक भू-स्खलन की धटना के कारण ये सीमेंट के पाईप जगह जगह से टूट व मिटट्री से अवरूद्ध हो गई , जिससे जगह - जगह पर पानी रिसने के कारण व्यर्थ होने लगा। ये सीमेंट के पाईप जमीन में कई जगह एक मीटर तक दबाए गए थे, जिससे इन पाईपों की मुरम्मत करना भी एक समस्या बन गयी। गठित की गई कमेटी की आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण इस

प्राकृतिक स्त्रोत से पानी की बूंद-बूंद इस गांव तक पहुंचाने के बाद अधिकतर भूमि सिंचित होने लगी व आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला। जो कृषक परियोजना से पहले 7000 रू वार्षिक कमाते थे वे अब 20,000 रू वार्षिक अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हो गए है।

गीता कुमारी, सुगमकर्ता, सुबाथु इकाई

सिंचाई योजना के अपने दम पर रख रखाव करने में वह असमंथ थी। अतः योजना ठप्प हो गई। इसके बावजूद भी ग्रामीण अपने खेतों तक पानी पंहुचाने का निरंतर असफल प्रयास करते रहें। वर्ष 1997.98 में सभी ग्रमवासियों ने एक बैटक की तथा आम सहमति बनी कि इस सिंचाई योजना को पौने इंच प्लास्टिक पाईप द्वारा पुर्नजीवित किया जाये । शीघ्र ही इस प्लास्टिक पाईप को बिछाया गया। सिंचाई योजना तो चल पडी परन्तु इसके द्वारा पानी इतना कम पहुंच पाता था कि गांव वासियों को सिंचाई तो दूर पशुओं के पानी का गुजारा भी नहीं हो पाता था। गांव में वार्षिक औसतन 3185 कि0 ग्रम टमाटर, 965 कि0 ग्रम शिमला मिर्च, 370 किलोग्रम मटर, 300 किलोग्रम खीरा 120 किलोग्रम गोभी, 200 किलोग्रम बीन्स का ही उत्पादन हो पाता था

वर्ष 2006-07 में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना सुबाथु इकाई सोलन मण्डल ने काम करना शुरु किया। गांव रामपुर भलोरी में परियोजना ने ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के निर्माण हेतु उप ग्राम सभा की बैठक की जिसमें लोगो ने इस गावं में सिंचाई समस्या को प्रमुखता से उठाया व शर्त रखी की इस समस्या का समाधान करें तभी गांववासी परियोजना में सहयोग देगें। 3 अक्तुबर 2007 को ग्राम रामपुर में मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना के सहयोग से एक समान रूचि समूह को गठित किया गया। इसमें गांव के 25 परिवारों के लाभार्थी ने भाग लिया। इस समान रुचि समूह की कार्यकारणी का गठन किया गया तथा मुख्या नियम बनाए गए। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए हैंड वाल का निर्माण किया गया।

15 दिसम्बर 2007 को सुबाथु इकाई द्वारा विश्व बैंक मिशन के प्रतिभागीयों से समान रुचि समूह का परिचय कराया गया जिसमें अधिकारी गणों ने लोंगो को उन्नत

प्राकृतिक स्त्रोतो से पानी एकत्रीकरण द्वारा आर्थिक विकास

तरीकों को अपनाते हुये नगदी फसलों की खेती के विषय में तकनीकी जानकारी दी तथा विश्व बैंक के अधिकारियों ने गांववासियों को जारु नाले से लोहे के पाइप द्वारा सिंचाई योजना का आश्वासन दिया। सुबाथु इकाई द्वारा फरवरी 2008 में जारु जल स्त्रोत पर पानी को रोकने के लिए एक तकनीकी ढांचे (मक्कोवाल टाईप स्ट्रक्चर) का निर्माण शुरु किया गया, तथा मई - जून महीने तक लोहे के पाईप लगाने का कार्य भी कर दिया गया। ढांचे के अलावा जो पाईप फिक्स की गई वे इस समूह के द्वारा ही की गई । लाभार्थी समूह / समान रुचि समूह द्वारा उक्त परियोजना के रखरखाव के लिए बैंक में 7000 रु की राशी जमा करवाई गई जिसमें से 1346 रुपये ग्राम पंचायत के मुरम्मत खाते में जमा करवाए गए।

मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना सुबाथु इकाई द्वारा समान रुचि समूह को उक्त सिंचाई योजना अर्पित करके कृतार्थ किया। सभी गांव वासी राहत की सांस लेने लगे नकदी फसलों के प्रति इकाई द्वारा प्रोत्साहित किया गया। व उन्नत किस्म के बीज (टमाटर शिमला मिर्च लहसून मेथी धनिया मटर) 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए गए जो एक सराहनीय कदम था ।

गीता कुमारी, सुगमकर्ता, सुबाथु इकाई

विशेष उपलब्धियां

1 आधुनिक परिवेश में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की महत्वता को देखते प्रबन्धन एवं सूचना पद्धति (एम.आई.एस.) व वित्तीय प्रबन्धन पद्धति (एफ.एम. एस.) को विकसित एवं स्थापित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर परियोजना को गतिशीलता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

2 तीन गाद व वर्षा मापक स्वचालित इलेक्ट्रानिक यंत्रों से युक्त सिल्ट ऑबजरवेशन पोस्टों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों की मदद से परियोजना द्वारा विभिन्न जलागम विकास एवम् उपचार गतिविधियों के पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक विधि से मूल्यांकन व विश्लेषण किया जा सकेगा।

3 परस्पर सम्पर्क के लिये परियोजना में अधिकाधिक इलेक्ट्रानिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है।

4 विभिन्न सूचनाओं से सुशज्जित परियोजना की बैव साईट का लोकार्पण कर दिया गया है।

5 बायो कार्बन उप योजना का सैंद्धान्तिक प्रारूप से प्रान्तिक दास्तावेज तैयार कर लिया गया है।

6 पशुपालन एवं जलागम विकास कार्यों की उल्लेखनीय प्रगति के लिये परियोजना को विश्व बैंक से विशेषकर प्रशंसा प्राप्त हुई है।

7 इन्जिनियरिंग मैनुवल Mannual को तैयार किया गया है।

8 परियोजना का आकर्षक त्रैमासिक पत्र आरम्भ कर दिया गया है।

9 पारदर्शिता के प्रति वचनबद्धता के लिय सभी प्रकार के लेनदेन में नगदी का प्रचलन पुर्णता बन्द कर दिया गया है।

10 परियोजना के विवेचना के लिये सहभागी मूल्यांकन आरम्भ हो गया है।

11 बायो कार्बन उप-योजना का सफलता पूर्वक मूल्यांकन करवाया गया।

12 विश्व बैंक ने मध्य हिमालय जलागम परियोजना को एक आदर्श परियोजना से परिभाषित किया है।

13 श्रेष्ट जलागम ग्राम पंचायत पुसस्कारों को आरम्भ कर वितरण किया गया है ।

14 परियोजना को बायो कार्बन उप योजना के लिये रूस के सैंट पिटर्सबर्ग में होने वाली कार्यशाला के लिये रिर्सोस परियोजना के तौर पर चयनित किया गया है।

इन दिनों

इस त्रिमाही में प्रस्तावित कार्यक्रम रू.

1 माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कारों का शिमला के ऐतिहासिक गेयटी सभागार में 8 अगस्त, 2009 को पुरस्कारों का भव्य समारोह में वितरण।

2 21 अगस्त, 2009 माननीय वन मन्त्री हिमाचल प्रदेश द्वारा परियोजना की प्रगति की समीक्षा।

3 विश्व बैंक एवं ईकोनोमिक अफेयर मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परियोजना की संयुक्त समीक्षा।

4 राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान फरीदाबाद में उप.निदेशक प्रशासन, द्वारा वित्तीय प्रबन्धन पर 7 सितम्बर से 18 सितम्बर, 2009 तक विशेष प्रशिक्षण।

अधिक जानकारी के लिये लॉग आन करें

www.hpmidhimalayan.org

प्रधान श्रीमति प्रेम कुमारी द्वितीय राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत जरी, विकास खण्ड एवं जिला कुल्लू

प्रधान श्री कर्म चन्द, तृतीय राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत कुन्नू, विकास खण्ड दरंग, जिला मण्डी

एक नजर...

प्रधान श्रीमति नीलम देवी, प्रथम राज्य स्तरीय श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार, शेरपुर विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा

श्रेष्ठ जलागम पंचायत पुरस्कार विजेता, श्री जगत प्रकाश नडड़ा, माननीय वन मन्त्री एव श्री आर0के0कपूर, मुख्य परियोजना निदेशक के साथ

सह.स्वर

आप सभी पाठकों से सप्रेम अनुरोध है कि इस पत्रिका एवं परियोजना से सम्बधित जो भी सुझाव व विचार आप के पास हो उसे हमें निसंकोच प्रेषित करें। आप के अमुल्य सुझाव व विचार हमें नये आयामों से अवगत करवायेंगे। परियोजना से सम्बधित अपने अनुभव भी सांझा करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

परियोजना जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना
फोरेस्ट कम्पलैक्स,टैंक रोड़ ,सोलन ;हि0प्र0-पिन .173212

अधिक जानकारी के लिए लॉग आन करें www.hpmidhimalayan.org

सम्पादक मण्डल

1. मुख्य सम्पादक	श्री आर0के0कपूर,भा0व0से0 मुख्य परियोजना निदेशक
2. उप.सम्पादक	श्री अरविंद, भा0व0से0 कार्यकारी निदेशक
3. सह.सम्पादक	श्री टी0 सी0 कौण्ड़ल, हि0प्र0व0से0 परियोजना जन सम्पर्क अधिकारी